VISION IAS

www.visionias.in

SUBJECT:	Essay	Test Code:		7	7	0
Name of Candidate	P. Yadav					
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	0 2 3 9 6 5			
Center	MN	Date				

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Section-A

"राष्ट्रीय हितों का स्थान मानवीय हितों के बाद आना चाहिए।"

संवाद -1

राष्ट्रीय हित: इतिहास गवाह है कि जब-जब राष्ट्रों ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा, तब तब उन्होंने मानव विकास के उच्च प्रतिमान प्राप्त किये; यथा संयुक्त राज्य अमेरिका व जापान।

मानवीय हित: लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब-जब राष्ट्रों ने राष्ट्रीय हितों को मानवीय हितों से बड़ी ज्यादा वरीयता दी, तब-तब मानवता ने भयंकर त्रासदी झेली है; यथा: प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध।

संवाद - 2

राष्ट्रीय हित: शायद आप राष्ट्रीय हित को गलत नजरिये से देख रहे हैं। यह भी तो वास्तव में लोगों के हितों की ही तो पूर्ति करता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति से ही, तो मानवीय हित पूरे होंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

मानवीय हित: अच्छा! आप तो बड़े आदर्श की बात कर रहे हैं। ये कहां सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक राष्ट्र के लोगों के हित / राष्ट्रीय हित वृहद मानवीय हितों की पूर्ति करेंगे? क्या मूल्य विहीन राष्ट्रीय हित यथा; राज्य प्रायोजित आतंकवाद, आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति का अनियंत्रित दोहन मानवीय हित पूर्ति है?

संवाद - 3

राष्ट्रीय हित: आपकी बात भी सही है, लेकिन क्या मैं यह मान लूं कि हमेशा ही राष्ट्रीय हितों की तिलांजलि / गौणता पर ही मानवीय हित पूर्ति होगी?

मानवीय हित: ऐसा नहीं है। मूल्यों से सरोकार रखने वाले राष्ट्रीय हित ही तर्कविस्तारित होकर वृहद स्तर पर मानवीय हितों का रूप लेते हैं। दोनों का एकाकार होना ही आदर्श लक्ष्य है।

उपरोक्त संवाद से दोनों के सार्थक तर्कों को तो समझा जा सकता है लेकिन विषय को समग्रता से समझने के लिए इस पर पर्याप्त विमर्श की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सर्वप्रथम, यह जानना आवश्यक है कि दोनों का आशय क्या है। राष्ट्रीय हित से तात्पर्य, एक राष्ट्र अर्थात् साझा मूल्यों यथा: नस्ल; इतिहास, भाषा इत्यादि के नाम पर भावनात्मक लगाव रखने वाले लोगों के हितों, से है जहां भौगोलिक सीमाएं हो भी सकती हैं या उनसे इतर भी राष्ट्रीय हित हो सकते हैं उदाहरण के लिए, विश्व के विभिन्न भागों में फैले होने के बावजूद सभी भारतीयों के हित एक समान हैं यथा; आर्थिक हित, मूल्य इत्यादि।

वहीं मानवीय हित से आशय है कि वृहद मानवीयता के संदर्भ में वो यथोचित दशाएं व परिस्थितियां जो मानव को सभी संकीर्ण बंधनों से मुक्त करके केवल मानव होने के नाते उसके हित में जो सर्वोच्च है, उसको प्राप्त करने की पेशकश करें। उदाहरण के लिए स्वच्छ पर्यावरण, शांतिप्रिय व सकारात्मक विकास, पारस्परिक सौहार्द व भाईचारा इत्यादि।

अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रीय हितों का स्थान मानवीय हितों के बाद आना चाहिए। अधिकांश लोग इस बात से सहमत

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भी है क्योंकि राष्ट्रीय हित केवल एक जैसी राष्ट्रीयता रखने वाले लोगों के हितों से सरोकार रखते हैं। और इसी तरह अलग-अलग राष्ट्र के अपने-2 अलग हित हो सकते हैं यथा; उत्तर कोरिया का हित सैन्य शक्ति में हो सकता है, तो दक्षिण कोरिया का हित आर्थिक विकास में। ऐसे में कई बार राष्ट्रीय हितों में संघर्ष भी हो सकता है। इसकी पुष्टि हम प्रथम विश्व युद्धोपरांत जर्मनी के संदर्भ में देखते हैं जहाँ यहूदियों व जर्मनों के हित परस्पर संघर्षरत थे।

इतना ही नहीं, इन राष्ट्रीय हितों के आलोक में विभिन्न राष्ट्र केवल अपने आर्थिक हितों को वरीयता देकर वृहद स्तर पर अप्रतिस्पर्धी माहौल ही नहीं पैदा करते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का भी निर्ममतापूर्वक असतत दोहन करते हैं।

राष्ट्रीय हित के नाम पर कई बार अल्पसंख्यक धर्मों, नस्लों, या अन्य विविधता वाले लोगों के मानवीय हितों का शोषण किया जाता है यहाँ अमानवीय व्यवहार किया है, चाहे वह औपनिवेशिक कालीन रंगभेद नीति हो, वर्तमान कालीन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद।

इससे भी बढ़कर विडम्बना तो तब देखने को मिलती है जब पृथ्वी व प्रकृति जो हमारे लिए जीवनदायिनी है, उसके प्रति भी राष्ट्रों का रवैया उपेक्षापूर्ण हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मन (ग्लोबल वार्मिंग), ओजोन क्षरण, बढ़ता प्रदूषण इत्यादि मुद्दों पर तथाकथित विकसित व सभ्य राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को वरीयता देकर वृहद मानवीय हितों के प्रति उत्तरदायित्व लेने से पीछे हट जाते हैं। उदाहरण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के प्रति राष्ट्रों का रवैया।

वर्तमान प्रौद्योगिकीय विश्व में राष्ट्रीय हितों के लिए शस्त्रीकरण, उपग्रह निगरानी, निजता का हनन, तकनीकी का दुरुपयोग जन-संहार के हथियार बनाने में, क्रूरता इत्यादि से मानवीय मूल्यों; जीवन, गरिमा, निजता इत्यादि को संकट में डाल रहे। चाहे वो 'ड्रोन' के माध्यम से की जाने वाली जासूसी हो या फिर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा निर्मित परमाणु हथियार।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ये तमाम आयाम बताते हैं कि यदि इस धरा को मानव विकास व अस्तित्व के लिए जीवंत रखना है तो दृष्टिकोण को मानवीय बनाना होगा तथा मानवीय हितों को सर्वोपरि रखकर वरीयता देना होगा।

हितों का वरीयता क्रम →

व्यक्ति → परिवार → समाज → राष्ट्र → विश्व
॥
वृहद मानवता

आधुनिकता की अवधारणा ने 'मानव' को परिधि से हटाकर केन्द्र में स्थापित कर दिया है। प्रत्येक गतिविधि अब मानवीय हित और कल्याण को केन्द्र में रखकर उसके सरोकार के लिए आयोजित की जाती है। यथा; तकनीकी विकास का उद्देश्य परमाणु बम बनाकर कुछेक संकीर्ण राष्ट्रीय वर्चस्व को प्राप्त करना नहीं होना था बल्कि वृहद मानव कल्याण की अपेक्षा थी।

निश्चित ही मानवीय हित वरीयता क्रम में हमेशा प्रथम आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर जब भी विमर्श होता है तो किसी राष्ट्र विशेष के हितों को ध्यान नहीं रखा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जाता है बल्कि मानवीय हितों को रखा जाता है। एक राष्ट्र की गलती की सजा हम पूरी मानवता को नहीं दे सकते हैं यहां विकसित व विकासशील और तटीय द्वीपों के हित अलग होते हैं लेकिन सभी को सहयोग करना होगा। अपेक्षित रहा है। विकसित राष्ट्र केवल समानता की बात नहीं कर सकते हैं उनको मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए वित्त व तकनीक का हस्तांतरण अविकसित व विकासशील राष्ट्रों को करना होगा।

इसी तरह शरणार्थी संकट जिसने लगभग पूरा मध्य एशिया व उत्तरी अफ्रीका की अस्थिर परिस्थितियों को जन्म दिया है को केवल इन राष्ट्रों की चिंता कहकर या फिर राष्ट्रीय हितों के नाम पर उनको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है और उसकी जीवन रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। यहां मानवता ही प्राथमिकता होनी चाहिए। समर्थ राष्ट्रों को दो तरफा कार्रवाई करनी होगी - एक तरफ इन अस्थिर राष्ट्रों को स्थिरता व शांति स्थापित करने में सहयोग करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

और इसका इन शरणार्थियों को यथासंभव मदद - जीवन सुरक्षा व आजीविका सुनिश्चित करना। इसी मानवता का ही एक सटीक उदाहरण है - जर्मनी। जिसने यहूदियों के प्रति किए गए अपने अमानवीय व क्रूर व्यवहार के लिए सार्वजनिक माफी मांगी है और शरणार्थियों को सहर्ष स्वीकार करके ऐतिहासिक भूल को सुधारने का प्रयास किया है।

इतना ही नहीं, आज के वैश्वीकृत विश्व में जब प्रत्येक चीज वैश्विक हो गयी है - वस्तुएं, श्रम, पूंजी इत्यादि, ऐसे में समस्याएं भी वैश्विक हैं और उनका मानवीय समाधान ही सार्थक हो सकता है। 'बीमारियां' (इबोला जिका इत्यादि), 'आपदा' (भूकंप, सुनामी, बढ़ता जल स्तर, वैश्विक तापन इत्यादि), विभिन्न जनित खतरा (परमाणु, ओज़ोन क्षरण इत्यादि) 'आतंकवाद' (USA पर हमला, पेरिस हमला, मुंबई पर हमला व हाल में लीबिया में ISIS इत्यादि) इत्यादि समस्याएं आज किसी राष्ट्र की सीमाओं में बंधकर नहीं रह गयी है बल्कि पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए संकट है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसलिए सभी को मिलकर इनके निवारण हेतु रणनीति बनाना है क्योंकि ये राष्ट्रीय हितों व सीमाओं को ~~बेवजह~~ लांघकर प्रत्येक मानव के लिए खतरा हैं

इतना ही नहीं, जब एक बड़ी आबादी सिर्फ इसलिए मर रही है कि अपनी दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति उचित कीमत पर नहीं हो पा रही है और इसके लिए उत्तरदायी हैं- राष्ट्रों की पेटेंट नीतियां व संकीर्ण आर्थिक हित। ऐसे में जेनेरिक दवाएं मानवीय हितों के लिए अपनानी ही पड़ेंगी। यहां मानवीय जीवन की रक्षा ही अहम है।

मानवीय हित ही हैं जो सतत विकास, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा व नैतिकता को स्थापित करते हैं क्योंकि जब तक पड़ोस में अस्थिरता, हिंसा, भूख, गरीबी है, तब तक कोई भी राष्ट्र शांति से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

विश्लेषण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय हितों से बढ़कर मानवीय हित हैं जो मानव मात्र की बात करते हैं "वसुधैव कुटुम्बकम्" "जीओ और जीने दो" का पैगाम देता है।

लेकिन एक दूसरा भी पक्ष है कि जब तक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम मानवीय हितों की सोच भी नहीं सकते हैं और यदि सोचेंगे तो भी वह केवल आदर्श होगा।

आज जापान, रूस, इत्यादि राष्ट्र वैश्विक समस्याओं के प्रति सकारात्मक सहयोग कर पा रहे हैं तो यह तभी संभव हो पाया है जब उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों को कुछ समय के लिए वरीयता प्रदान की।

यदि जापान ने अपने विकास के लिए एकांतवाद को न चुना होता या औद्योगिक विकास न किया होता तो आज वह सुनामी जैसी त्रासदी के लिए तकनीकी क्षमता हासिल न कर पाता जो पूरी मानवता को त्रासदी से बचा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इतना ही नहीं, यदि राष्ट्रवाद के नाम पर इटली व जर्मनी का एकीकरण न हुआ होता, तो आज यूरोप हिंसा से ग्रस्त होता।

आज यूरोप तभी शरणार्थियों को आश्रय दे पा रहा है जब पहले उन राष्ट्रों ने अपने-2 लोगों की मूल व दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया है।

राष्ट्रीय हित के नाम पर ही सोवियत संघ संगठित रह पाया था और जैसे ही उसने उदारता व वृहद मानवीय मूल्यों को जगह दी वह खण्ड खण्ड होकर बिखर गया।

इसलिए कई बार राष्ट्रीय हित को वरीयता देकर भी वृहद स्तर या दीर्घावधि में मानवीय हित को बचाया जा सकता है लेकिन एक ऐसा प्रश्न अभी इसमें भी निहित है कि क्या एक मूल्य विहीन राष्ट्रीय हित अर्थात् संकीर्ण राष्ट्रवाद को वरीयता स्थान दिया जा सकता है?

वो राष्ट्र जो आतंकवाद को प्रायोजित करते थे, आज वही राष्ट्र आतंकवाद की आग में जल रहे हैं,

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

संकीर्ण धार्मिक भावनाओं की आड़ में राष्ट्रीय हित साधने की कामना रखने वाले आज उन्हीं धार्मिक स्थलों, स्कूलों इत्यादि पर आतंक खेल रहे हैं।

दूसरी ओर, कुछ राष्ट्रों की जनता भूख से मर रही है और राष्ट्रीय हित के नाम पर लाखों टन अनाज गोदाम में फेंका जा रहा है (आर्थिक कारण) तो क्या हम इसे राष्ट्रीय हित नहीं कह सकते हैं।

इससे भी बड़ी चिंता है जलवायु शरणार्थी जो निश्चित ही कुछ राष्ट्रों के आर्थिक विकास के असतत होने का परिणाम हैं। उन्हीं के अपने द्वीप आज जलवायु शरणार्थी के लिए खतरा हैं।

उपरोक्त तमाम उदाहरण दिखाते हैं कि मूल्यविहीन व मानवीय हित विरोधी राष्ट्रीय हित वास्तव में राष्ट्रीय हित हैं ही नहीं। अल्पकाल में ये कुछ राजनीतिक प्रतिष्ठान जनता को राष्ट्रीय के नाम पर बरगला सकते हैं लेकिन दीर्घकाल में ये स्वयं उस राष्ट्र व मानवीय हितों के लिए खतरा हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समग्र आयामों पर चर्चा उपरांत अब हम निष्कर्ष पर आए हैं कि यदि राष्ट्रीय हितों व मानवीय हितों के बीच की टकराव स्थिति है या वरीयता की नैतिक दुविधा उत्पन्न करती है तो निश्चित ही सभी राष्ट्रों को मूल्ययुक्त राष्ट्रीय हितों को अपनाना होगा। जो एक वैश्विक नैतिक ढांचे से मार्गनिर्देशित होंगे।

एक वैश्विक नैतिक ढांचा जो समता, न्याय, स्वतंत्रता, सर्वहित कल्याण, मानवीय गरिमा, सतत् विकास, पर्यावरणीय स्वच्छता, खुशहाल जीवन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व व सभी विवादों को आपसी संवाद, विश्वास व मानव हित के आलोक में निपटने को युक्त है। तभी राष्ट्रीय हित व मानवीय हित का भेद / दुविधा सदा के लिए मिट जाएगी

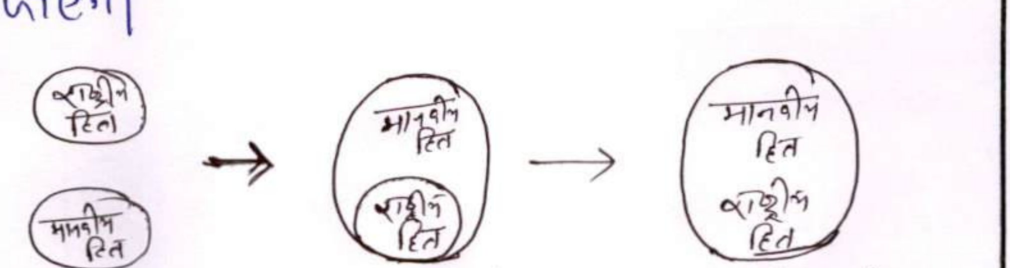

स्थिति-प्रथम स्थिति-द्वितीय स्थिति-तृतीय

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थिति - वृतीय ही सभी लाइलाज बीमारियों का सटीक इलाज है जो मानव को मानवता के नाम पर संबोधित करती है। तभी हम कह पाएंगे —

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु; मा कश्चित दुःख भाग भवेत।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Section-B.

"राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त के प्रतिपादन हेतु यह एक उचित समय है।"

1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना करके राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की पहल शुरु होने से लेकर 1999 में 'न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु निवारक सिद्धान्त' के तहत प्रथम इस्तेमाल न करने की नीति, 2004 के 'आर्मी सिद्धान्त' बनाये जाने ~~पर~~ जैसे तमाम प्रयास में अधा-धुरा राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त बनाने की चर्चा होती रही है।

26/11 के मुम्बई के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का देरी से पहुंचना, सही तरीके से घटनाक्रम का कवरेज न करने ने इस मुद्दे को फिर हवा दी, कि यदि भारत को संतुलित राष्ट्रीय सुरक्षा चाहिए तो एक समग्र व एकीकृत 'सिद्धान्त' आवश्यक है।

लेकिन जनवरी 2016 के पठानकोट हमले ने तो इस मांग को सियासी गलियारों से लेकर, बौद्धिक वर्ग और सुरक्षा विशेषज्ञों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

~~हर~~ हर तरफ विमर्श का मुद्दा बना दिया कि आखिर हर बार हमारे प्रत्युत्तर / प्रतिक्रिया में चूक क्यों हो जाती है? क्यों खुफिया सूचनाओं को नजरअंदाज किया गया? क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को पहुंचने का इंतजार किया, जब स्थानीय प्रशिक्षित जैन्य (?) इकाइयाँ स्थल पर ही मौजूद थे? इतना ही नहीं, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न इस प्रतिक्रिया की नाकामी का जिम्मेदार किसे माना जाए?

उपरोक्त तमाम प्रश्नों का एक ही उत्तर हो सकता है और वह है - "राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त" का न होना। विषय की गंभीरता के चलते विशेषज्ञों ने इसे उचित समय बताया है लेकिन कुछ चिंताएँ भी जाहिर की हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं की चर्चा ही हमारे विमर्श का विषय है।

सर्वप्रथम, यह जानना आवश्यक है कि आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त' से आशय क्या है? 'सिद्धान्त' - नीति का एक घोषित नियम' होता है ~~जो~~ जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा

एक व्यापक सुरक्षा अवधारणा है। सामान्य रूप में यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें सरकार / संसद द्वारा देश की भौगोलिक अखण्डता, संप्रभुता, सर्वांगीण आयामों पर विदेशों से आर्थिक व राजनीतिक संबंध स्थापना के साथ-साथ "राष्ट्रीय संकट" (National crisis) के समय अपने राज्य व इसके नागरिकों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराये। इसके लिए राजनीतिक व सैन्य ताकत, कूटनीति, तकनीकी, आर्थिक क्षमताओं व जन विश्वास इत्यादि का उचित समन्वय व सहयोग लिया जा सकता है।

वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बहुआयामी दृष्टिकोण में शामिल हैं- आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा के वातावरण के साथ-साथ अन्तर्संबंधित खतरे व निहितार्थ।

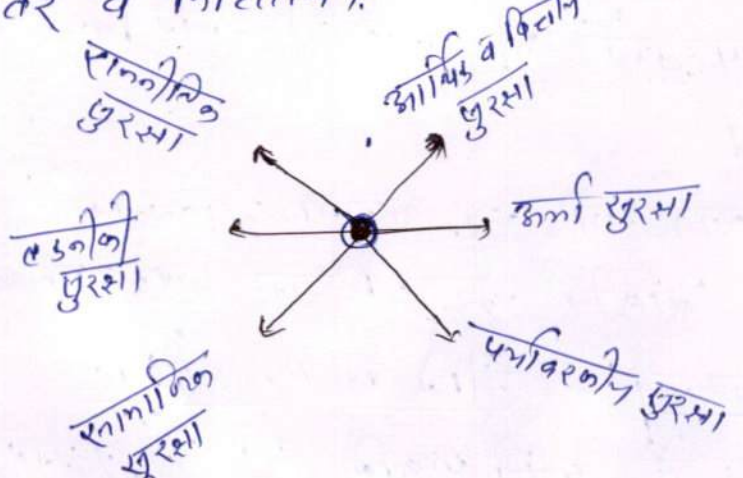

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वरूप 1991 के वैश्वीकरण के उपरांत बहुत ही विस्तृत हो गया है तथा चुनौतियाँ भी काफी गंभीर है।

स्वरूप		खतरे	
परम्परागत	गैर-परम्परागत	राज्य जनित	गैर राज्य कर्ता
सीमा विवाद	साइबर सुरक्षा	बाहरी राज्य	ड्रग माफिया
प्रायोजित आतंकवाद	मानव तस्करी	कूटनीतिक दबाव	बहुराष्ट्रीय कंपनियां
आंतरिक अशांति	ड्रग तस्करी	सामाजिक आर्थिक नीतियां	कुछेक NGO
गंभीर असमानतायें	जाली नोट	इत्यादि	हिंसक तत्व
इत्यादि	इत्यादि		संगठित अपराध इत्यादि।

राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान चुनौतिपूर्ण स्थिति, को निपटने के लिए इसके साथ 'सिद्धान्त' का जुड़ना आवश्यक है - "राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त"।

'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त' वास्तव में यह एक घोषित सरकारी नियमों वाला सरकारी नीतिगत दस्तावेज है जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर आसन्न खतरे के आलोक में रणनीतिक व परिचालनात्मक संबंधी मार्गनिर्देशन करता है। यह विभिन्न

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परिस्थितियों (खतरों) के संदर्भ में विभिन्न रणनीतियों, युक्तियों व विशिष्ट संचालन व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। अर्थात् यथा एक आतंकवादी हमले के दौरान कार्रवाई – खुफिया तंत्र की आसूचना लेना, उचित प्रतिक्रिया दल की त्वरित कार्रवाई, विभिन्न एजेंसियों में समन्वय व निश्चित जवाबदेहिता तय करना।

अब चर्चा का मुद्दा है कि आखिर इस 'सिद्धान्त' की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- वैश्वीकृत विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आक्रमण का अप्रत्याशित रूप से घटना यथा; शेयर मार्केट पर आर्थिक हमला, साइबर हमले में सामरिक महत्त्व की जानकारी चुराना, जाली नोटों व ड्रग्स तस्करी से आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था को हिलाना, आंतरिक असंतुष्ट वर्गों व संगठनों को बाह्य/ प्रायोजित सहायता, सोशल मीडिया इत्यादि पर नयी सुरक्षा चुनौतियाँ।
- सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने समय उचित कार्रवाई का चयन न करना यथा 26/11 मुम्बई व पठानकोट हमला।

- सूचना व आसूचना तंत्र का अन्तःसंबंध न होना तथा सूचना जानकारियों की उपेक्षा किया जाना।
- सुरक्षा एजेंसियों के मध्य समन्वय की भारी कमी होने के कारण अनावश्यक नुकसान उठाना।
- असफलता के बाद किसी की भी कानूनी व नैतिक जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित न किया जाना इत्यादि।

उपरोक्त चिंताओं को समायोजित करते हुए 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त' व्यापक समग्र व एकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य करेगा। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु पूर्णता के साथ देश की सैन्य शक्ति, कूटनीतिक प्रयासों, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक हथियारों के साथ तकनीकी का अनुप्रयोग होगा जो राष्ट्र न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा बल्कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को भी बढ़ाएगा।

- यह संकट के समय त्वरित व सार्थक निर्णय के एक उचित कार्रवाई का चयन करने में सहायक होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

- तत्काल उचित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्णय राष्ट्रीय सिद्धान्त में निहित रणनीति अनुरूप लिए जाएंगे।
- केन्द्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित सुरक्षा अभिकरणों के मध्य तालमेल को बनाकर एकीकृत कार्रवाई करना यथा; राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के साथ स्थानीय पुलिस का संवाद बढ़ाना।
- खुफिया आसूचनाओं के एकीकरण व परिष्करण हेतु 'नेटग्रिड' जैसी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करके सही समय पर सूचना संबंधित संस्थाओं तक साझा करेगा।
- सुरक्षा अभिकरणों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करके उनको अधिक क्रियाशील व अनु-सक्रिय बनाएगा।

उपरोक्त कार्रवाईयों का का शीघ्र व सफल संचालन देश में शांति, विकास एवं उन्नति को बढ़ाएगा।

किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त के व्यापक निहितार्थ होते हैं। इसको हम एक जीवंत उदाहरण से समझ सकते हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

और वो है - अमेरिका। वहां पर प्रत्येक राष्ट्रपति अपना प्रशासन संभालते ही सर्वप्रथम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की घोषणा करता है यथा; जॉर्ज बुश की नीति - 'अचानक किए जाने वाले हमले तथा शासन पद्धति में परिवर्तन'

वहीं ओबामा सरकार ने एक नव बनावटी दृष्टिकोण अपनाया जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्रीय अखण्डता, कूटनीतिक संबंधता, आर्थिक अनुशासन व जनता में मेल-जोल बढ़ाने वाली नीति अपनाई।

उपरोक्त दोनों नीतियों ने अपने-2 तरीके से अमेरिका की स्थिरता, वर्चस्व व राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया है।

यही आवश्यकता आज भारत को है। जब तमाम दिशाओं में खतरे मुंह बाए खड़े हों तब ऐसी उचित 'सिद्धान्त' को अपनाना और भी अपरिहार्य हो जाता है।

लेकिन एक प्रश्न अभी अधूरा रह गया है - कि क्या केवल 'सिद्धान्त' अपने आप में पर्याप्त है? इसके सही उत्तर के लिए हमें एक आयाम को सिद्धान्त में और

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

जोड़ना होगा और वह है - "राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति" तभी हमारा उत्तर पूर्ण होगा। 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति' इस सिद्धान्त का व्यवहारिक धरातल पर अनुप्रयोग सुनिश्चित करेगी। इसमें आदेश व नियंत्रण का एक संगठित ढांचा उपलब्ध होगा आतंकी हमले जैसे हालात से निपटने की रणनीति बताएगा।

वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त व राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति मिलकर ही समग्रता से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी।

एक विचारणीय विषय है कि क्या अभी 'उचित समय' आ गया है कि भारत को यह सिद्धान्त अपनाना चाहिए, तो इसका होगा - बहुत हद तक आ गया है। पूर्णता से लाने के लिए कुछेक चुनौतियों को संबोधित करना बाकी है।

आज भारत के पास पर्याप्त तकनीक, रक्षा सामग्री व मानव संसाधन के साथ-2 सशक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नजर आ रही है। इसका साक्षात उदाहरण है -

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उरी आर्मी बेस पर हमले के प्रत्युत्तर में की गयी 'सर्जिकल स्ट्राइक', जो तैयारी, तकनीक व इच्छाशक्ति तीनों का उच्च स्तरीय संगठन था।

आकृत्ववा के लिए भारत के पास RAW, IB के साथ-साथ 'नेटग्रिड' प्रणाली भी उपलब्ध है और साथ स्थानीय पुलिस व मुखबिरों का भी एक संगठित ढांचा उपलब्ध है।

कार्रवाई के स्तर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, आर्थिक अपराध सेल, सीमा पार तस्करी पर ध्यान रखने वाले प्रशिक्षित कर्मी, आतंकी हमलों से निपटने हेतु विशिष्ट प्रशिक्षित सैन्य बल, नक्सलियों, स्थानीय उग्रवादियों इत्यादि से निपटने हेतु विशिष्ट आरक्षित बटालियन, साइबर हमलों से निपटने हेतु कम्प्यूटर रिस्पॉन्स टीम व नैटरो जैसे संगठन के साथ ही हाल में विचाराधीन साइबर सुरक्षा संगठन उपलब्ध होंगे जो अपने-2 क्षेत्र में आतंकवादियों का पूर्ण विशेषज्ञता से सामना कर पाएंगे।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

साथ ही अन्वेषण हेतु 'राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी' व स्थानीय पुलिस की विशेष यूनिटें भी कार्यरत हैं।

दोषियों को सजा हेतु अवैधानिक गतिविधियां निवारण अधिनियम में नये संशोधन करना, मकोका, गुजकोका जैसे स्थानीय कानून व आतंकवाद विरोधी कानून (पोटा इत्यादि) इत्यादि के तहत एक व्यवस्थित ढांचा उपलब्ध है।

तमाम वैधानिक, तकनीक के साथ समर्पित मानव संसाधन व जनता का सक्रिय सहयोग व राजनीतिक इच्छा शक्ति भी अपने चरम पर है इसका जीवंत व ज्वलंत उदाहरण है - हाल ही की नोटबंदी। जाली मुद्रा रोकने व काला धन जनित अपराध रोकने की दिशा में एक संगठित कार्रवाई।

लेकिन अभी भी कुछ चिंताएं हैं जो सिद्धान्त को व्यवहारिक बनाने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यथा; तकनीकी की अपर्याप्तता - साइबर आक्रमण के समय, बाहरी खतरों के आलोक में रक्षा सामग्री की पर्याप्तता पर भी सन्देह है, केन्द्र व राज्यों

के बीच अभी भी उचित संवाद (सुरक्षा) व समन्वय का अभाव। अभी तक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का अभी भी आकार न ले पाना।

'नेटग्रिड' द्वारा राज्य पुलिस को सही समय पर सूचना उपलब्ध न कर पाना। साथ ही जनता को भी इन सुरक्षा चुनौतियों के बारे में पर्याप्त जागरूकता व न्यूनतम प्रशिक्षण का अभाव है।

हमारी सीमाओं को अभी भी ज्यादा चौकस व नेटवर्कड करने की आवश्यकता है। सुरक्षा में तकनीकी व प्रौद्योगिकी का पर्याप्त इस्तेमाल न किया जाना।

- सबसे बढ़कर बाधा अभी तक सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा विषय को गंभीरता न लिया जाना है।

इन सब बाधाओं के आलोक में एक अग्र-सक्रिय कार्रवाई करते हुए सभी हितधारकों के सक्रिय योगदान प्राप्त करने व बेहतर सुझाव पाने हेतु जागरूकता बढ़ाना, राजनीतिक दलों में पारस्परिक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सहमति बनाना, सिद्धान्त में पारदर्शिता बनाकर इसकी स्पष्ट घोषणा करना, इसे व्यापक व समग्रता देना ताकि आवश्यक सभी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करे। पठानकोट, उरी, 26/11 जैसी दिल दहलाने वाली घटनाओं की पुनरावृती रोकने हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाने व तकनीकी क्षमता का अनुकूलन सुरक्षा तंत्रों में बनाना अत्यावश्यक है।

भारत ने बहुत ही सही समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशीलता और नजाकत को देखते हुए 'राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धान्त' की चर्चा शुरू की है। आवश्यकता है कथाकथित बाधाओं को संबोधित करते हुए यथाशीघ्र इसे आकार देना और मॉक ड्रिल इत्यादि से इसकी व्यवहारिकता को जाँचना। निश्चित ही यह भारत को शांति, सुरक्षा व विकास के लिए एक स्थिर आवरण देगा जिसमें कोई भी नापाक ताकत प्रवेश नहीं कर पाएगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

"भारत देश तैयार है,
नित-नित आगे बढ़ने को।
कर सुरक्षा सुनिश्चित,
विकास को समग्र बनाने को।।"

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)